

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4337

दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

टाइप-2 मधुमेह के मामले

†4337. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 15-24 वर्ष की आयु के युवाओं में टाइप-2 मधुमेह (टी2डी) के मामलों में बढ़ोत्तरी का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
- (ख) क्या सरकार के पास युवाओं में टाइप-2 मधुमेह के प्रसार के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश में युवाओं में मधुमेह के बारे में जागरूकता और रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए क्या विशिष्ट पहल की जा रही हैं;
- (घ) क्या युवाओं में मधुमेह के शीघ्र निदान और उपचार में सुधार के लिए कोई लक्षित कार्यक्रम हैं और यदि हां, तो ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में मधुमेह के प्रबंधन के लिए उचित स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए किए गए प्रयासों की स्थिति क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मानव संसाधन विकास, शीघ्र निदान, उपचार और प्रबंधन के लिए उचित स्तर के स्वास्थ्य परिचर्या केंद्र के लिए रेफरल और मधुमेह सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है। 1,75,182 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से सभी के लिए मधुमेह

के जोखिम का आकलन और जांच की जाती है। राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत 770 जिला एनसीडी क्लिनिक और 6410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लिनिक स्थापित किए गए हैं।

मधुमेह सहित एनसीडी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए आगे की पहलों में विश्व मधुमेह दिवस मनाना, निरंतर सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग करना शामिल है। मधुमेह सहित एनसीडी के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रमों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए "ईट राइट इनिशिएटिव" और "आज से थोड़ा कम" जैसे अभियान शुरू किए हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित "फिट इंडिया मूवमेंट" और "खेलो इंडिया" युवाओं को शारीरिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि सेवा पहल के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर सभी को इंसुलिन सहित मधुमेह के लिए आवश्यक दवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) का लक्ष्य लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है, जो भारत की आबादी के निम्नतम 40% हिस्से में आने वाले 12.37 करोड़ परिवारों से संबंधित है।

स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) के नवीनतम राष्ट्रीय मास्टर में इस योजना के अंतर्गत 29,870 से अधिक अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से मधुमेह और मधुमेह के कारण उत्पन्न जटिलताओं सहित 27 स्पेशलिटी में 1961 प्रक्रियाओं से संबंधित कैशलेस स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मधुमेह से उत्पन्न जटिलताओं से संबंधित कुछ पैकेजों में डायबिटिक फुट, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक रेटिनोपैथी आदि शामिल हैं।
